भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1472
गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना की प्रगति

1472. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उड़ान योजना की प्रगति से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक शुरू किए गए वायु मार्गों की कुल संख्या कितनी है और उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में वर्तमान में कितने वायु मार्ग चालू हैं;

(ग) साधारण जन के लिए विशेषकर सुदूर और अल्पविकसित क्षेत्रों की आम जनता के लिए वहनीय हवाई यात्रा विकल्पों को बढ़ाने के संदर्भ में उक्त योजना का प्रभाव क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त योजना को कार्यान्वित करने में आने वाली चुनौतियों के संबंध में एयरलाइंस और यात्रियों से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बढ़ती परिचालन लागत और बड़ी एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा के विशेष संदर्भ में उड़ान योजना वाले वायु मार्गों को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार और अधिक गंतव्यों को शामिल करने और विद्यमान वायु मार्गों पर सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के विशेष संदर्भ में आगामी वर्षों में उक्त योजना में कोई विस्तार या संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) देश में विमानन अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से सुदूर और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की गई थी। इस योजना में वैध बोली प्रक्रिया के माध्यम से असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को चिह्नित करके और चिह्नित हवाईअड्डे को जोड़ने वाले मार्ग को परिचालित करने हेतु चयनित एयरलाइन प्रचालक को अवार्ड करके उनके पुनरुद्धार/उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

योजना के आरंभ होने के बाद से अब तक 88 असेवित और अल्पसेवित हवा अड्डों (13 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 619 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया जा चुका है।

वर्तमान में, इस योजना के तहत तमिलनाडु में आठ (08) मार्ग परिचालित हैं।

उड़ान योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतों के माध्यम से चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को सहायता देकर, ताकि क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन की लागत को कम किया जा सके और इस अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण या वीजीएफ) सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क की वहनीयता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है ।

(घ) से (च) उड़ान एक चल रही योजना है, जिसके तहत समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इस योजना को बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने तथा परिचालन संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए विकसित और अनुकूलित किया गया है। उड़ान 5.0 में देश के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा का सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करते हुए उच्च दक्षता और परिचालन संधारणीयता को सक्षम करने के लिए योजना प्रावधानों में प्रणालीगत परिवर्तन किए गए। इसके परिणामस्वरूप, उड़ान योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 2.96 लाख आरसीएस उड़ानों से 149 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उड़ान योजना के मार्ग वित्तीय रूप से संधारणीय बने रहें, परिचालन अंतर को पूरा करने के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालक को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान किया जा रहा है, साथ ही योजना के प्रावधानों के अनुसार, आवंटित मार्गों पर हवाईअड्डा प्रचालक और राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष की एक्सक्लूजिविटी (अनन्यता) और अन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं।

सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित उड़ान योजना आरंभ करने की घोषणा की है।

*****